



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

6 श्रावण 1933 (श0)  
(सं0 पटना 370) पटना, वृहस्पतिवार, 28 जुलाई 2011

---

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

28 जुलाई 2011

सं0 एल0जी0-6-01/2011-151/लेज—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का अधिनियम 2) की धारा-357-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, केन्द्र सरकार के समन्वय से, पीड़ित अथवा उसकी आश्रितों को, जो अपराध के परिणामस्वरूप हानि या क्षति से पीड़ित हो अथवा जिन्हें पुनर्वास की जरूरत हो, प्रतिकर के प्रयोजनार्थ निधि का उपबंध करने के लिए निम्नलिखित स्कीम गठित करते हैं यथा:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरंभ ।—(1) यह स्कीम बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011 कही जा सकेगी ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह तुरत प्रवृत्त होगी ।

2. परिभाषाएँ ।—इस स्कीम में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो ।

(क) “अधिनियम” से अभिप्रेत है दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2);

(ख) “अनुसूची ” से अभिप्रेत है इस स्कीम से उपाबद्ध अनुसूची;

(ग) “राज्य ” से अभिप्रेत है बिहार राज्य;

(घ) “पीड़ित” से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जो स्वयं ऐसे अपराध के परिणामस्वरूप हानि या क्षति से पीड़ित हो जिससे परिवार की आय की सारवान् हानि हुई हो जिसके चलते बिना वित्तीय सहायता, उनका जीवन-यापन कठिन हो गया हो अथवा मानसिक/शारीरिक क्षति का चिकित्सा निदान पर खर्च उसकी क्षमता के बाहर हो और जिसे पुनर्वास की जरूरत हो तथा इसमें परिवार के आश्रित सदस्य शामिल है ।

(ड०) “आश्रित” से अभिप्रेत है पीड़ित के परिवार के सदस्य यथा पति-पत्नी, माता-पिता, भाई-बहन, पुत्र-पुत्री, दादा-दादी, सास-ससुर और अन्य कोई व्यक्ति जो पीड़ित की आय पर जीवन निर्वाह करता हो।

3. पीड़ित प्रतिकर निधि ।—(1) पीड़ित प्रतिकर निधि नामक एक निधि गठित की जायगी जिससे इस स्कीम के अधीन प्रतिकर की राशि पीड़ित अथवा उसके आश्रितों को जो अपराध के परिणामस्वरूप हानि अथवा क्षति से पीड़ित हों और जिन्हें पुनर्वास की अपेक्षा हो, दी जायगी ।

(2) राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष इस स्कीम के प्रयोजनार्थ एक पृथक बजट आवंटन करेगी ।

(3) इस निधि का प्रवर्तन सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा किया जायेगा।

(4) राज्य सरकार, सड़क दुर्घटना और गंभीर उपहति के अन्य मामलों में पीड़ित को तीव्र और तुरंत चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए पुलिस स्टेशन के स्तर पर निधि गठित करने हेतु पीड़ित प्रतिकर निधि से उतनी राशि आबंटित कर सकेगी जो उचित समझे। ऐसी निधि का प्रवर्तन संबंधित थाना प्रभारी द्वारा किया जायेगा।

4. प्रतिकर के लिए पात्रता ।—कोई भी पीड़ित प्रतिकर के अनुदान के लिए पात्र होगा, यदि—

(क) अपराधी का पता न चले अथवा उसकी पहचान न हो किंतु पीड़ित की पहचान हो जाय और जहाँ कोई विचारण न हुआ हो वहाँ ऐसा पीड़ित भी अधिनियम की धारा-357-क की उप-धारा (4) के अधीन प्रतिकर के अनुदान के लिए आवेदन कर सकेगा।

(ख) पीड़ित/दावा करने वाला अपराध का रिपोर्ट थाना प्रभारी अथवा क्षेत्र के न्यायिक मजिस्ट्रेट को तत्परता से देगा परंतु जिला विधिक सेवा प्राधिकार, यदि उनका समाधान हो जाय, लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, रिपोर्ट करने में विलम्ब की माफी दे सकेगा ।

(ग) पीड़ित/दावा करने वाला मामले के अनुसंधान और विचारण के दौरान पुलिस और अभियोजन के साथ सहायता करेगा ।

5. प्रतिकर के अनुदान के लिए प्रक्रिया ।—(1) जिला विधिक सेवा प्राधिकार को जब कभी किसी न्यायालय द्वारा अनुशंसा की जाय अथवा किसी पीड़ित अथवा उसके आश्रित द्वारा अधिनियम की धारा-357-क के अधीन कोई आवेदन दिया जाय तो जिला विधिक सेवा प्राधिकार मामले का परीक्षण करेगा और पीड़ित को हुई हानि या क्षति के संबंध में तथा प्रतिवेदित आपराधिक क्रियाकलाप से उत्पन्न दावे के अंतर्वस्तुओं का सत्यापन करेगा तथा असलियत को विनिश्चित करने के लिए किसी अन्य सुसंगत आवश्यक जानकारी की मांग कर सकेगा। दावा का सत्यापन करने के बाद, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सम्यक् जाँच-पड़ताल के बाद, स्कीम के प्रावधानों के अनुसार दो माह के भीतर प्रतिकर देगा।

(2) इस स्कीम के अधीन प्रतिकर इस शर्त के अधीन दिया जायगा कि यदि विचारण न्यायालय, किसी बाद की तिथि को फैसला देते समय, अधिनियम की धारा-357-क की उप-धारा (3) के अधीन प्रतिकर के रूप में कोई राशि देने के लिए अभियुक्त व्यक्ति को आदेश देता है तो पीड़ित दावाकर्ता प्रतिकर की राशि के समतुल्य आदेशित राशि अथवा अधिनियम की धारा-357-क की उक्त उप-धारा (3) के अधीन दी जाने वाली आदेशित राशि, जो भी कम हो, छोड़ देगा, प्रतिकर राशि वितरण के पूर्व पीड़ित/दावाकर्ता द्वारा उसके संबंध में एक वचनबंध दिया जायगा।

(3) जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पीड़ित अथवा उसके आश्रितों को दिये जाने वाले प्रतिकर की राशि, दाह संस्कार आदि व्यय के रूप में आनुषंगिक प्रभार सहित, पीड़ित को हुई हानि, उपचार पर उपगत चिकित्सा व्यय, पुनर्वास के लिए अपेक्षित न्यूनतम जीवनयापन की राशि के आधार पर, विनिश्चित करेगा। प्रतिकर में, प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करते हुए, एक मामले से दूसरे मामले में अंतर आ सकेगा।

(4) इस स्कीम में दिये जाने वाले प्रतिकर की राशि इस स्कीम की अनुसूची के अनुसार यथास्थिति, पीड़ित अथवा उसके आश्रितों को इस निधि से वितरित की जायेगी ।

(5) केन्द्रीय/राज्य सरकार, बीमा कंपनी प्रश्नगत अपराध के संबंध में किसी अन्य संस्था, यथा-बीमा, अनुग्रह और/अथवा किसी अधिनियम अथवा राज्य द्वारा चल रही स्कीम के अधीन प्राप्त भुगतान इस स्कीम के अधीन प्रतिकर की राशि के भाग के रूप में समझा जायेगा और यदि पात्र प्रतिकर राशि, उपर्युक्त सांपारिर्वाक श्रोतों से पीड़ित द्वारा प्राप्त भुगतान से अधिक हो तो अतिशेष राशि निधि से दी जायेगी ।

(6) प्रतिकर की राशि नियत करने में, न्यूनतम मजदूरी और मोटर यान अधिनियम, 1988 की अनुसूची का ध्यान रखा जायगा।

(7) जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पीड़ित की यातना में कमी करने के लिए, तुरत फर्स्ट एड सुविधा के लिए अथवा संबंधित क्षेत्र पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी की पंक्ति से अन्यून पुलिस अफिसर के प्रमाण-पत्र पर मुफ्त चिकित्सा लाभ उपलब्ध कराने अथवा किसी अन्य अंतरिम राहत देने हेतु, जिसे उचित समझे, आदेश कर सकेगा।

6. आदेश का अभिलेख पर रखा जाना ।- इस स्कीम के अधीन पारित प्रतिकर के आदेश की प्रति, अधिनियम की धारा-357-क की उप-धारा (3) के अधीन प्रतिकर का आदेश पारित करने वाले न्यायालय को समर्थ करने हेतु, विचारण न्यायालय के अभिलेख पर आज्ञापकरूप से रखी जायेगी ।

7. समय सीमा ।- अधिनियम की धारा-357-क की उप-धारा (4) के अधीन पीड़ित अथवा उसके आश्रितों द्वारा किये गए किसी दावे को अपराध के छह माह की अवधि के बाद ग्रहण नहीं किया जायेगा:

परंतु जिला विधिक सेवा प्राधिकार यदि उसका समाधान हो जाय, लिखितरूप में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से दावा दाखिल करने के विलंब को माफ कर सकेगा ।

8. अपील ।-जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा प्रतिकर की इनकारी से व्यथित कोई पीड़ित, इनकारी के आदेश की तिथि से गणना की गयी 90 (नब्बे) दिनों की अवधि के भीतर, राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के समक्ष अपील दायर कर सकेगा:

परंतु राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, यदि उसका समाधान हो जाय, लिखितरूप में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, अपील दाखिल करने में विलंब को माफ कर सकेगा ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
विनोद कुमार सिन्हा,  
सरकार के सचिव ।

#### अनुसूची देखे कंडिका-5(4)

क्र०सं०	हानि अथवा क्षति की विशिष्टियाँ	प्रतिकर की अधिकतम सीमा रुपये
1	बलात्कार	50,000
2	मानव दुर्व्यवहार अपहरण आदि जैसे मामले में पीड़ित महिला एवं बच्चे को गंभीर मानसिक दर्द पहुँचाने वाली हानि अथवा क्षति ।	25,000
3	जीवन की हानि	1,00,000
4	भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा-320 में यथा परिभाषित गंभीर उपहति	25,000
5	एसिड आक्रमण द्वारा की गयी क्षति ।	25,000

28 जुलाई 2011

सं० एल०जी०-6-01/2011-152/लेज, सं० 151 दिनांक 28 जुलाई 2011 का निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड(3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उक्त अधिसूचित स्कीम, 2011 का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा,

सरकार के सचिव ।

*The 28th July 2011*

No. L.G.-6-01/2011-151/leg—In exercise of the powers conferred by section 357-A of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974), the Governor of Bihar in co-ordination with the Central Government, hereby frames the following scheme for providing funds for the purpose of compensation to the victim or his dependents who have suffered loss or injury as a result of the crime and who require rehabilitation, namely:-

1. *Short title, extent and Commencement.*—(1) This scheme may be called the Bihar Victim compensation Scheme, 2011.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

2. *Definition.*—In this scheme, unless the context otherwise requires, -

(a) "Act" means the code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974);

(b) "Schedule" means Schedule appended to this Scheme;

(c) "State" means State of Bihar;

(d) "Victim" means a person who himself has suffered loss or injury as a result of crime causing substantial loss to the income of the family making it difficult to meet their both ends without the financial aid or has to spend beyond his means on medical treatment of Mental/Physical injury and require rehabilitation.

(e) In this scheme "Dependent" means member of family of the victim, namely Husband/Wife, Mother/Father, Brother/Sister, Son/Daughter, Grand Mother/Grand Father, Father-in-Law/Mother-in-Law and it includes any other person who is leading life on the income of the victim.

3. *Victim Compensation Fund.*—(1) There shall be constituted a fund, namely, Victim Compensation Fund, from which amount of compensation under this Scheme shall be paid to the victim or his dependents who have suffered loss or injury as a result of the crime and who require rehabilitation.

(2) The State Government shall allot a separate budget for the purpose of the Scheme every year.

(3) The fund shall be operated by the Secretary, State Legal Services Authority.

(4) The State Govt. may allocate such amount, as it think proper, out of victim compensation fund, to constitute a fund at Police Station level for providing quick and immediate Medical Assistance to the victim of road accident and other cases of grievous hurt. Such fund shall be operated by concerned Officer-in-charge.

4. *Eligibility for Compensation.*—A victim shall be eligible for the grant of compensation if, —

(a) the offender is not traced or identified, but the victim is identified, and where no trial takes place, such victim may also apply for grant of compensation under sub section (4) of section 357-A of the Act,

(b) the victim/claimant report the crime to the Officer-in-charge of Police Station or Judicial magistrate of the area promptly provided that the District Legal Service Authority, if satisfied, for the reasons to be recorded in writing, may condone the delay in reporting;

(c) the victim/claimant co-operates with the police and prosecution during the investigation and trial of the case.

5. *Procedure for grant of compensation.*—(1) Whenever a recommendation is made by the Court or an application is made by any victim or his dependent under sub section (4) of section 357-A of the Act to the District Legal Service Authority, the District Legal Service Authority shall examine the case and verify the contents of the claim with regard to the loss or injury caused to victim and arising out of the reported criminal activity and may call for any other relevant information necessary in order to determine genuineness. After verifying the claim, the District Legal Service Authority shall after due enquiry award compensation within two months, in accordance with provision of the Scheme.

(2) compensation under this Scheme shall be paid subject to the condition that if the trial court while passing judgment at later date, orders the accused persons to pay any amount by way of compensation under sub-section (3) of section 357 of the Act, victim/claimant shall remit an amount ordered equal to the amount of compensation, or the amount ordered to be paid under the said sub-section (3) of section 357 of the Act, whichever is less. An undertaking to this effect shall be given by the victim/claimant before the disbursement of the compensation amount.

(3) The District Legal Service Authority shall decide the quantum of compensation to be awarded to the victim or his dependents on the basis of loss caused to the victim, medical expenses to be incurred on treatment, minimum sustenance amount required for rehabilitation including such incidental charges as funeral expenses etc. The compensation may vary from case to case depending on facts of each case.

(4) According to the schedule of this scheme the quantum of compensation to be awarded under the Scheme shall be disbursed to the victim or his dependents, as the case may be, from the Fund.

(5) Compensation received by the victim from the Central/State Govt., Insurance company or any other institution in relation to the crime in question, namely, insurance, ex-gratia and/or payment received under any other Act or State-run Scheme, shall be considered as part of the compensation amount under these scheme and if the eligible compensation amount exceeds the payments received by the victim from collateral sources mentioned above, the balance amount shall be paid out of the Fund.

(6) In fixing the quantum of compensation, regard must be had to the minimum wages and the schedule to the Motor vehicle Act, 1988.

(7) The District Legal Service Authority, to alleviate the suffering of the victim, may order for immediate first aid facility or medical benefits to be made available free of cost on the certificate of the police officer not below the rank of the Officer-in-charge of the police station or magistrate of the area concerned, or any other interim relief as it may deem fit,

6. *Order to be placed on record.*—Copy of the order of compensation passed under this Scheme shall be mandatorily placed on record of the trial Court to enable the court to pass order of compensation under sub-section (3) of section 357 of the Act.

7. *Limitation.*—No claim made by the victim or his dependents under sub-section (4) of section 357-A of the Act shall be entertained after a period of six months of the crime:

Provided that the District Legal Service Authority, if satisfied, for the reasons to be recorded in writing, may condone the delay in filing the claim.

8. *Appeal.*—Any victim aggrieved of the denial of compensation by the District Legal Service Authority may file an appeal before the State legal Service Authority within a period of ninety days computed from the date of order of denial:

Provided that the State Legal Service Authority, if satisfied, for the reasons to be recorded in writing, may condone the delay in filing the appeal.

By order of the Governor of Bihar,  
VINOD KUMAR SINHA,  
Secretary to Government.

**SCHEDULE***See Para 5(4)*

<b>Sl. No.</b>	<b>Particulars of loss or injury</b>	<b>Maximum limit of compensation Rs.</b>
1	Rape	50,000
2	Loss or injury causing severe mental agony to women and child victims in case like Human Trafficking, Kidnapping etc.	25,000
3	Loss of life.	1,00,000
4	Grievous hurt as defined in section 320 of the Indian Penal Code, 1860.	25,000
5	Injury caused by acid attack.	25,000

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
 बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
 बिहार गजट (असाधारण) 370-571+500-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>